BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

सहकार से समृद्धि

भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के पांच साल

06 जुलाई 2026

भारत की सहकारी यात्रा : सामूहिक विकास में निहित

भारत का सहकारी आंदोलन *वसुधैव कुटुम्बकम* के दर्शन में गहराई से निहित है। *वसुधैव कुटुम्बकम* एक ऐसा दर्शन जिसमें पूरी दुनिया एक परिवार है। सहकारी समितियों ने लंबे समय से साझा स्वामित्व, आपसी समर्थन और समावेशी विकास के संस्थानों के रूप में कार्य किया है। ग्रामीण ऋण से लेकर डेयरी, मत्स्य पालन, आवास और विपणन तक, सहकारी समितियों ने लाखों लोगों को बाजारों, वित्त और आजीविका तक पहुंचने के काबिल बनाया है। 6 जुलाई, 2021 को स्थापित **सहकारिता मंत्रालय** संस्थानों को मजबूत करके और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करके **सहकारी क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता** को उजागर करने के लिए **सरकार की प्रतिबद्धता को** दर्शाता है।

डिजिटल और संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाना

सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस **6 जुलाई, 2026** को भारत मंडपम, नई दिल्ली में मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख डिजिटल और बुनियादी ढांचा पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से भारत के सहकारी परितंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इन पहलों में **50,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को** ई-पैक्स में बदलने का मुख्य आकर्षण शामिल रहा।

इस कार्यक्रम में सहकारी भंडारण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए **47 अनाज भंडारण गोदामों** की आधारशिला भी रखी गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के लिए एक दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया था ताकि दूध की खरीद और वितरण के प्रबंधन में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (एनयूसीएफडीसी) की दो प्रमुख पहलों – **सहकार सीबीएस** और **सहकार सहयोगी का अनावरण किया गया**। सहकार सीबीएस शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक केंद्रीकृत कोर बैंकिंग समाधान है। सहकार सहयोगी एक संवादात्मक एआई-संचालित मंच है जिसे ग्राहक सेवाओं और बैंकिंग संचालन को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।

भारत में सहकारी समितियां: एक नज़र

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े सहकारी परितंत्र में से एक है, जो अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये संस्थान जमीनी स्तर पर आर्थिक भागीदारी की रीढ़ हैं, जो किसानों, डेयरी उत्पादकों, मछुआरों, कारीगरों और श्रमिकों को आय के अवसरों से जोड़ते हैं।

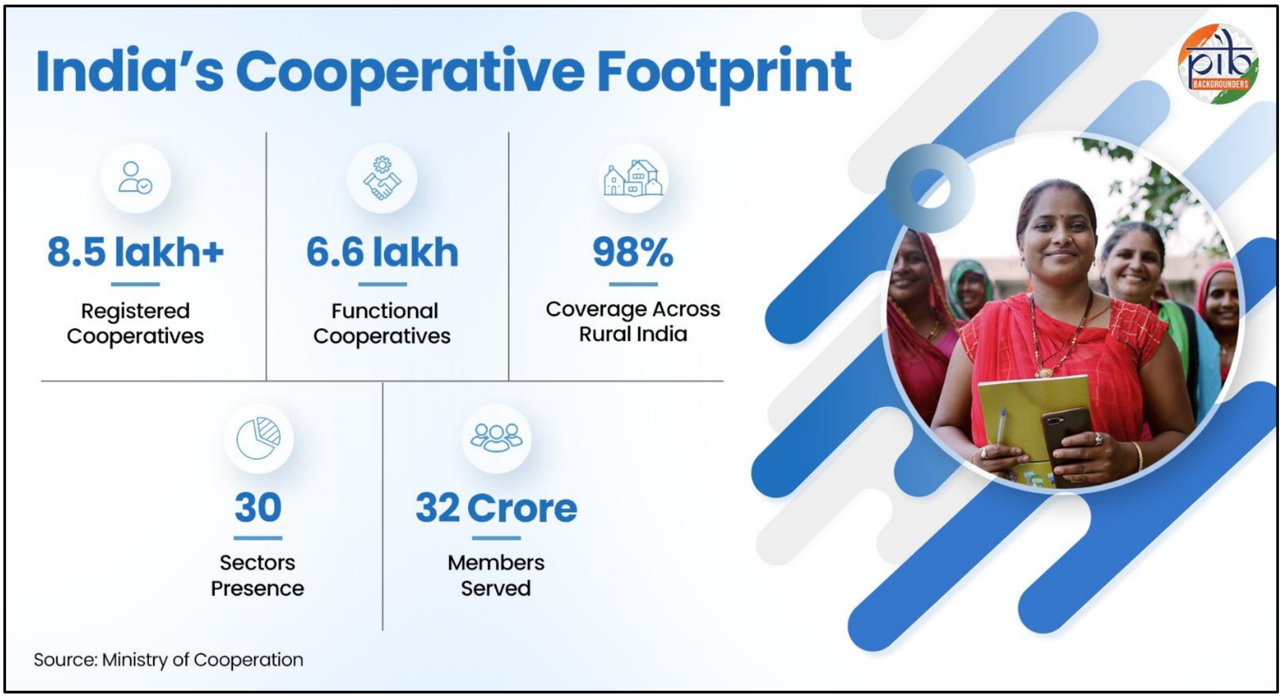

संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत करना

पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने देश के सहकारी परितंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार किए हैं। ये सुधार सहकारी समितियों को अधिक समावेशी, पारदर्शी, डिजिटल रूप से सशक्त और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने पर केंद्रित रहे हैं। इन प्रयासों ने सहकारी समितियों को जमीनी स्तर की समृद्धि और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के मजबूत इंजन के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद से अब तक 152 **से अधिक प्रमुख पहल** शुरू की गई हैं। इन पहलों ने विकास और विविधीकरण के नए अवसर पैदा करते हुए पारंपरिक सहकारी संस्थानों का आधुनिकीकरण किया है।

1. पैक्स को पुनर्जीवित करना: ऋण संस्थानों से लेकर ग्रामीण विकास केंद्रों तक

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस - पैक्स) अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जमीनी आधार बनाती हैं। वे सक्रिय रूप से **बहु-सेवा संस्थानों** के रूप में कार्यरत हैं जो ग्रामीण आर्थिक सेवाओं के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

जून 2026 तक पैक्स की सेवा के लिए हुई मुख्य प्रगति इस प्रकार है:

1. मॉडल उप-नियम 32 **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों** में पैक्स को 25+ **व्यावसायिक गतिविधियां** करने में सक्षम बनाते हैं।
2. **पैक्स अब** रिटेल, स्टोरेज, हेल्थकेयर, फ्यूल और डिजिटल सेवाओं को कवर करते हुए **क्रेडिट से परे काम करता है।**
3. 394 पैक्स ने खुदरा ईंधन दुकानों के लिए आवेदन किया है, और 3 आउटलेट चालू किए गए हैं।
1. 39,177 पैक्स **पीएम किसान समृद्धि केंद्रों** के रूप में कार्य कर रहे हैं।
1. 54,117 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं।
2. जन औषधि केंद्रों **के लिए 4,248 पैक्स** स्वीकृत किए गए हैं; 843 पैक्स कार्य करने के लिए तैयार हैं।

इस विविधीकरण ने ग्रामीण स्तर पर आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है।

2. पैक्स का डिजिटल परिवर्तन

सहकारी शासन और दक्षता को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रीय साधन बन गई है। जून 2026 तक पैक्स के डिजिटलीकरण में निम्नलिखित प्रगति हुई है:

1. कुल वित्तीय परिव्यय 2022 में 2,516 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन से बढ़ाकर **2025 में 2,925.39 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।
2. 63,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की समय सीमा **31 मार्च**, 2027 तक है।
3. 79,630 पैक्स को मंजूरी दी गई; 63,428 पैक्स वर्तमान में ईआरपी सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं।
4. 65 हजार से अधिक पैक्स को हार्डवेयर पहुंचाया गया।
5. 42,700 से अधिक पैक्स में ऑनलाइन ऑडिट पूरा किया गया।
6. ईआरपी सॉफ्टवेयर 14 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

पैक्स के डिजिटलीकरण से **पारदर्शिता, लेखांकन और सेवा वितरण** में काफी सुधार हुआ है।

3. जमीनी स्तर पर सहकारी कवरेज का विस्तार

सरकार ने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है कि प्रत्येक पंचायत सहकारी संस्थाओं से जुड़ी हो:

1. अब तक 37,454 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां पंजीकृत की गईं।
2. 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में पैक्स मौजूद हैं।
3. डेयरी सहकारी समितियों में 87,159 से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
4. मत्स्य सहकारी समितियों में 29,964 से अधिक ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

यह विस्तार वंचित क्षेत्रों में सहकारी पहुंच को मजबूत कर रहा है।

4. सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण

सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से **दुनिया की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना** भी लागू कर रही है:

1. 145 पैक्स में गोदाम पूरे हुए
2. सृजित भंडारण क्षमता: 68,702 मीट्रिक टन से अधिक

यह पहल फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और स्थानीय भंडारण तथा बेहतर बाजार समय को सक्षम करके किसानों की आय में सुधार करने में मदद करती है।

5. किसान-उत्पादक संस्थानों (एफपीओ) को मजबूत करना

बेहतर एकत्रीकरण और बाजार पहुंच के लिए **सहकारी समितियों को** आधुनिक किसान समूहों के साथ एकीकृत किया जा रहा है:

1. सहकारी क्षेत्र में 1,863 एफपीओ का गठन
2. पैक्स के माध्यम से 1,117 एफपीओ बनाए गए
1. 1,070 मत्स्य पालन एफपीओ का गठन किया गया और उनके लाभ के लिए 98 करोड़ रुपये वितरित किए गए

इससे बाजार से जुड़ने, प्रसंस्करण और किसानों की आय प्राप्ति में सुधार हो रहा है।

6. कर राहत और व्यापार करने में आसानी

नीतिगत सुधारों ने सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति में भी सुधार किया है। सहकारी समितियों के लिए शुरू किए गए प्रमुख कर राहत उपाय हैं:

1. एक से 10 करोड़ रुपये के बीच आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया।
2. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
3. टीडीएस नकद निकासी की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये की गई।
4. पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए उच्च नकद लेनदेन सीमा।

इन उपायों ने तरलता में वृद्धि की है और अनुपालन बोझ को कम किया है।

7. श्वेत क्रांति 2.0

2028-29 तक दूध की खरीद को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए **श्वेत क्रांति** 2.0 के तहत सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है।

1. अब तक 25,282 डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
2. महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी सहकारी समितियों और व्यापक सहकारी कवरेज पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

8. नए राष्ट्रीय सहकारी संस्थान

क्षेत्र-विशिष्ट विकास को मजबूत करने के लिए, तीन नए राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी संस्थान स्थापित किए गए हैं, और उनकी प्रगति अब तक दर्ज की गई है:

1. **नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल)**: एनसीईएल देश भर में विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित **अधिशेष वस्तुओं/सेवाओं** के निर्यात के लिए एकछत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। एनसीईएल ने जून 2026 तक **38 देशों को** 6,295 **करोड़ रुपये मूल्य का** 15.4 **एलएमटी निर्यात** दर्ज किया।
2. **नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल)**: एनसीओएल जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणन, परीक्षण, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एकछत्र संगठन के रूप में कार्य करता है। जून 2026 तक इसमें 14,286 सदस्य सहकारी समितियां हैं।
3. **भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल)**: बीबीएसएसएल सहकारी नेटवर्क के माध्यम से **"भारत बीज" ब्रांड** नाम के तहत **गुणवत्ता वाले बीजों** का उत्पादन, खरीद और वितरण करता है। जून 2026 तक इसमें 38,665 सदस्य सहकारी समितियां हैं।

9. क्षमता निर्माण और सहकारी शिक्षा

सरकार शिक्षा और संस्थागत विकास के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत कर रही है। **त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (टीएसयू)** को भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। यह विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी)** और **नाबार्ड** के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। ये पहल सहकारी समितियों में शासन, नेतृत्व और परिचालन दक्षता को मजबूत करती हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम: निवेश बढ़ाने में संलग्न

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने सहकारी समितियों के विकास के वित्तपोषण में प्रमुख भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एनसीडीसी ने 1.55 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और 1.27 **लाख करोड़ रुपये वितरित किए हैं**। इसने **मई 2026 तक** 10,000 **एफपीओ के गठन और प्रचार** की योजना के तहत एफपीओ/क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को 2,320 **करोड़ रुपये** भी वितरित किए हैं। यह निरंतर वित्तपोषण सभी क्षेत्रों में सहकारी विस्तार को गति दे रहा है।

भारत टैक्सी: भारत का पहला सहकारी-आधारित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म

भारत टैक्सी **सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड** की एक पहल है। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड सहकारी मॉडल पर आधारित एक ड्राइवर-केंद्रित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य जनता को सस्ती, सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करते हुए ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

वर्तमान में, भारत टैक्सी में 6.37 **लाख पंजीकृत ड्राइवर** और 35.77 **लाख पंजीकृत ग्राहक हैं**। यह सेवा **दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर और कानपुर** में चालू है। अगले कुछ महीनों में **रांची, पटना, गुवाहाटी, भोपाल, कोलकाता, इंदौर और नागपुर** में परिचालन शुरू करने की योजना है।

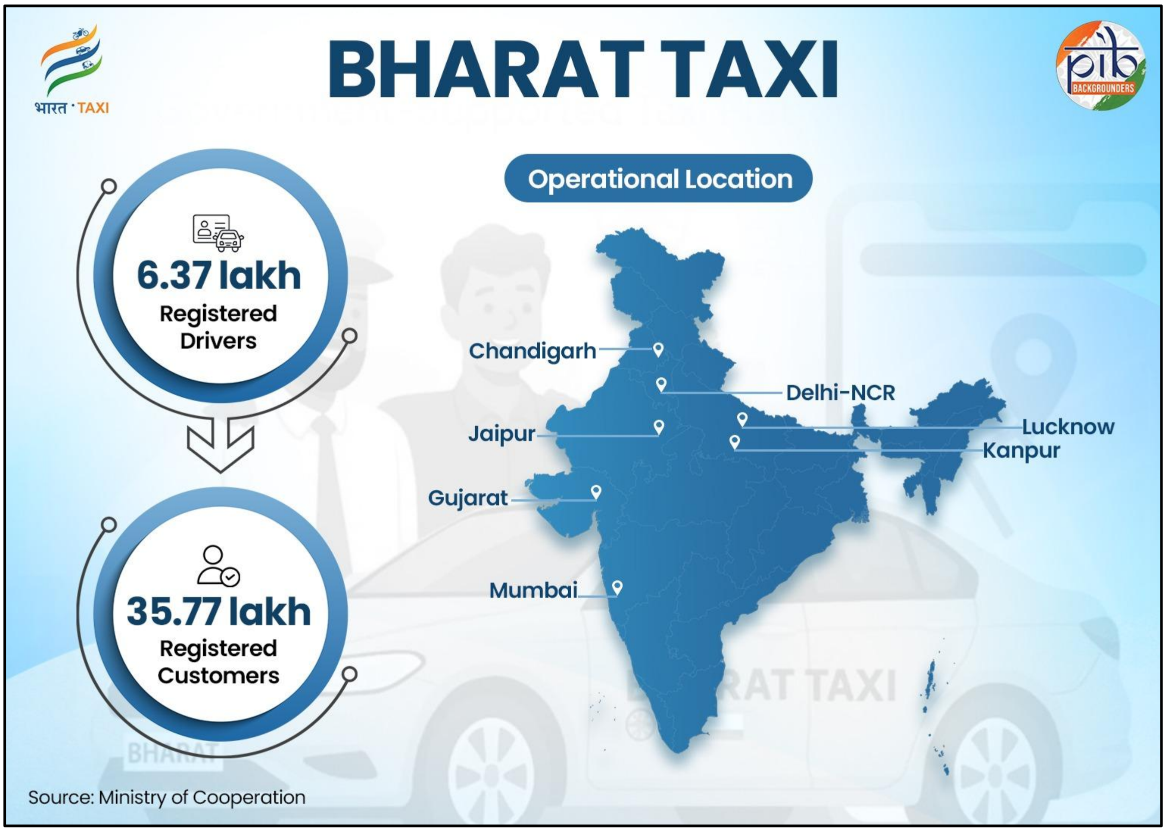

विकसित भारत को सशक्त बनाने वाली सहकारी समितियां

पांच साल में सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता को समावेशी विकास के इंजन में बदलने का काम किया है। मजबूत संस्थानों, बेहतर सेवा वितरण और व्यापक डिजिटल अपनाने से जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव बढ़ा है। विस्तारित बुनियादी ढांचे और बेहतर बाजार पहुंच ने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया है। सहकारिता के नेतृत्व में जारी विकास की वजह से महिलाओं और किसानों के पास अब अधिक अवसर हैं।

जैसे-जैसे भारत समावेशी और सतत विकास के अपने पथ पर आगे बढ़ रहा है, सहकारी समितियां समान विकास और लचीलेपन को बढ़ावा देना जारी रखेंगी। "**सहकार से समृद्धि**" के दृष्टिकोण से निर्देशित, सहकारी आंदोलन एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण कर रहा है।

संदर्भ

सहकारिता मंत्रालय

https://cooperation.gov.in/en/about-primary-agriculture-cooperative-credit-societies-pacs
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146717&reg=48&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241955&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2214633&reg=3&lang=2
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201729&reg=3&lang=1
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2281327&reg=48&lang=1
https://sansad.in/getFile/annex/270/AU4161_Yqq3fo.pdf?source=pqars

पीआईबी बैकग्राउंडर

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156980&ModuleId=3&reg=22&lang=13

पीआईबी रिसर्च

पीके/केसी/एके/एसवी